सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं
की बेहतरी को लेकर

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य अभियान

जनपद–बलिया

Yes Democracy

समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम, उ०प्र०

YES DEMOCRACY

स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं की बेहतरी को लेकर एक अभियान

अभियान अवधि- 29 अप्रैल से 15 सितम्बर 2019 तक

आयोजक

समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम, उ०प्र०

सहयोग

आक्सफाम इण्ड़िया, उ०प्र०

समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम के बारे में–

समवेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम का गठन

दलित, मुस्लिम और जनजातीय समुदायों का बहिष्कार गरीबी का एक केंद्रीय आयाम है। इन तीन समुदायों में %38आबादी और देश के गरीबों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। उपलब्धता, नियमितता और पर्याप्त सार्वजनिक सेवाओं, अवसरों तक पहुँचने में सेवा प्रदाताओं से विकास योजनाओं और बाधाओं से उनके बहिष्कार को देखते हुए, ये हाशिये पर पड़े समूह विभिन्न संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं। इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि इन तीन समुदायों के सदस्य अपनी मांग को मुखर करने में सक्षम हों और मुख्यधारा से जुड़ कर सेवा प्रदाताओं से बातचीत कर अपने मुद्दे रख सकें। पिछले दो दशकों से दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के नेतृत्व में सामुदायिक संगठन अपने समुदायों के प्रचलित विकास चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं और विकास और शासन प्रक्रियाओं में उनके समावेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में बढ़ रही गैर बराबरी विषमता और बुनियादी सुविधाओं में आदिवासियों, दलित और मुस्लिम सामाजिक श्रेणियां की भागीदारी और नेतृत्व विकास को ले कर Oxfam, CSEI और Praxis द्वारा संचालित सोशल इंक्लूजन प्रोजेक्ट की 2016 में शुरुआत की गई है | सोशल इंक्लूजन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में समवेशी स्वास्थ्य को लेकर चल रहे कार्यक्रम में समवेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम (SSS Forum) का गठन किया गया है। **समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम, उ0प्र0 वंचित समुदाय के स्वास्थ्य सेवाओ के बेहतरी, योजनाओ एंव नीतियो तक पहुॅच एंव भागीदारी को बढाने एंव विभिन्न स्तरो पर जन पैरवी को बढावा देने को लेकर काम करने वाली जमीनी स्तर की वंचित समुदाय द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्थाओ का एक नेटवर्क/मंच है।**

अभियान के बारे में–

लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र के महापर्व का आयोजन 17वीं लोक सभा के गठन का दौर संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग ने समस्त भारत में कुल सात चरणों में चुनाव कराने का निर्धारित तिथि एवं लोक सभा का चुनाव एक कुशल प्रबंधन के साथ आयोजित किया। चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर जनता के साथ जुड़कर कार्य करने वाले जन संगठनों ने निष्पक्ष एवं जनता के मुद्दों को चिन्हित करके समुदाय और प्रतिनिधि, एकेडमिक, कानूनीविद सामाजिक कर्मियों ने आपस में संवाद करके जनता के मांग पत्र का मसौदा तैयार किया। इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम संस्थान द्वारा 12 जनपदों में।

1. जालौन
2. हमीरपुर
3. कन्नौज
4. कानपुर
5. उन्नाव
6. जौनपुर
7. वाराणसी
8. गाजीपुर
9. बलिया
10. महाराजगंज
11. मऊ
12. लखनऊ

संसदीय क्षेत्रों का चयन किया इसके अन्तर्गत अपने अनुभव आधारित मुद्दा में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मुद्दे को 12 जनपदों के अन्तर्गत 50 पंचायत के 75 गांव एवं 10 प्रत्याशियों के साथ मिलकर कार्य करने का अभियान चलाया इस अभियान को 4 चरणों में बांट कर कार्य किया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

समुदाय यह जनता चाहती है, कि स्वास्थ्य व शिक्षा की सेवाएं जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, यह आवश्यकता हर आम और खास को निशुल्क मिलनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में प्रदेश में लागू किया गया, परन्तु इस अधिनियम का अभी तक आम जनता को कुछ खास लाभ नहीं मिल सका है। ठीक यही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का भी है, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी होना, दवाओं का न मिलना, अधिकतर दवाऐं मार्केट में डॉक्टर्स द्वारा लिखी जा रही हैं, यह आम जनता की पहुंच से दूर है। इन सेवाओं के देने के लिए सरकार को सरल नियम बनाने होंगे और इसमें गुणबत्ता पर भी ध्यान देना होगा।

समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम (SSS FORUM) उ0प्र0 एवं आक्सफैम इण्डिया तथा नव भारतीय नारी विकास समिति के निर्देशन में # yes democracy के अनुसार समस्त संस्थाओं इस कार्यक्रम को 4 हिस्सों में मुख्य आयोजन किया–

1. सामुदायिक जागरूकता/लामंबदी।
2. सामुदायिक मांग पत्र "मेरे बिल का भुगतान करो"।
3. राज्य स्तरीय पैरवी हेतू संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों तथा अन्य हित भागियों के साथ राज्य/क्षेत्रिय परामर्श कार्यशाला।
4. स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दे पर युवाओं की सहभागिता।

एवं साथ में अन्य गतिविधियां भी किया गया जो निम्न है–

वालेन्टीयर के साथ Orientation बैठक।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं में बेहतरी को लेकर तैयार घोषणा पत्र पर ब्लाक स्तरीय चर्चा।

स्वास्थ्य एंव शिक्षा के घोषणा पत्र पर समुदाय के साथ जागरूकता बैठक।

समुदाय के साथ मुद्दा आधारित मतदाता जागरूकता।

स्वास्थ्य अधिकार के मॉग पर हस्ताक्षर अभियान–

उम्मीदवारों/प्रत्याशियों के द्वारा स्वास्थ्य एंव शिक्षा के प्रतिबद्धता पत्रों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षर।

बेहतर स्वास्थ्य सेवा हेतु हस्ताक्षर अभियान।

"मेरे बिल का भुगतान करो" के अन्तर्गत अपने सासंद को पोस्टकार्ड भेजने का अभियान।

युवाओं के साथ संवाद।

सहयोगी संस्थाओं के साथ समन्वय।

सामुदायिक जागरूकता/लामंबदी–इसके अर्न्तगत 12 जनपदों में 09 साथी संस्था सदस्यों के द्वारा जनता का घोषणा पत्र, समुदायक मीटिंग एवं हस्ताक्षर अभियान कैम्पेन चलाया गया। जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर हस्ताक्षर किये। संस्था के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाये ? बताने का प्रयास किया।

12 साथी संस्था सदस्यों के द्वारा द्वारा चलाये गये हस्ताक्षर अभियान और बैठक में इस तरह के सवाल जनता द्वारा भी उठाये गये हैं। समावेशी समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम (SSS FORUM) की इस पहल से उ0प्र0 में स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं के प्रति लोग जागरूक हुए एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा भरा गया **प्रतिबद्धता पत्र** इस बात की गवाही देता है कि हमारे जन प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं शिक्षा से महरूम देश व प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है तथा चुनाव कैम्पेन के दौरान सभी प्रत्याशियों ने संस्था कार्यकर्ताओं को # yes democracy पर सरकार के समक्ष स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपने विचार रखने का भरोसा दिलाया है।

सामुदायिक मांग पत्र "मेरे बिल का भुगतान करो"–

इस कार्य में सहभागी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक जननद से 5 परीवार के ऐसे गम्भीर बिमारीयों से ग्रषित मरीजों जैसे कैंसर, किड़नी का खराब होना, कोमा इत्यादी में उस परिवार का बहुत सारा धन खर्चा हो जाता है उस परिवार को जमीन, मकान तक बेचना पड़ जाता है एवं वे कर्जे में डुब जातें है। ऐसे मरिजों के द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया, पोस्ट कार्ड में बिमारी का विवरण एवं खर्चे का विवरण देते हुये पुरे बिल की फोटो कापी सहित अपने सांसद को भेजा गया।

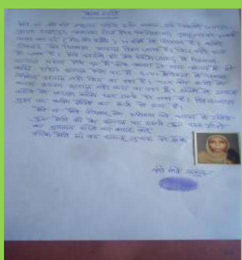

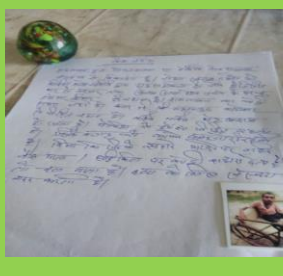

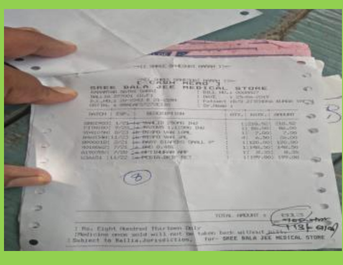

राज्य स्तरीय पैरवी हेतू संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों तथा अन्य हित भागियों के साथ राज्य/क्षेत्रिय परामर्श कार्यशाला–

सदस्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से 6 जनपदों में बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, जालौन एवं फिरोजाबाद में आयोजन किया गया जिसमें स्वाथ्य अधिकार को कैसे प्राप्त किया जाय पर गहन चर्चा किया गया जो निम्न है–

उ0प्र0 मे आज भी वंचित समुदाय के महिलाओ एंव बच्चो के स्वास्थ्य सेवाओ मे निरन्तर भेदभाव जारी है जिसके प्रमुख कारणो पर चर्चा करते हुये आपने बताया कि जातिगत एंव जेण्डरगत भेदभाव एंव सरकार की निष्क्रियता एक प्रमुख कारण है। उपरोक्त को निम्न प्रकार से देखा जाये तो अभी तक सरकार द्वारा कुल वजट का राष्टीय स्तर पर जन स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च मे जी0डी0पी का मात्र 1.28 प्रतिशत दर एंव उ0प्र0 मे 1.42 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है। और उसके अलावा अगर जनपद जौनपुर की स्वास्थ्य सेवाओ की स्थिति देखा जाये तो जनपद–जौनपुर मे मातृ मृत्युदर 281 है जबकि भारत का 130 है। शिशु मृत्युदर भारत का 33 है जबकि जनपद–जौनपुर का 75 है जिसमे 05 वर्ष के बच्चो का मृत्युदर जनपद– जौनपुर का 91 और भारत का 58 है। यह उपरोक्त आकडे दर्शाते है कि जनपद–जौनपुर मे स्वास्थ्य की स्थितियॉ बहुत ही समस्याग्रस्त एंव चिन्ताजनक है।

अक्सर देखा गया है कि जाति धर्म के आधार पर सभी क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है। जिससे गरीब वंचित समाज की महिलाएं बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है और सरकार नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास परन्तु ऐसा हो नहीं रहा है आज भी बड़े स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है इसलिए नीजि क्षेत्र का बढ़ावा मिल रहा है गरीब लोग पैसे के अभाव में अपनी जीवन लीला को खो बैठते है बच्चे महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते है इस सबपर रोक लगाने के लिए प्रत्येक देश राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश के नागरिकों की शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं निःशुल्क करें दोनां क्षेत्रों में काफी भ्रष्टाचार फैला है लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है साथ ही सरकार की अच्छी नीतियां भी बनाई गई है परन्तु जनता के हित में लागू नहीं किया जाता है ओर राजनीति की जाती है। सरकारी अस्पतालों में अनुभवी डाक्टरों नर्स विशेषज्ञों की कमी के कारण लोगों को नीजि क्षेत्रों में दाखिला कराकर इलाज कराते है बी0एच0यू0 एवं ए0एम0एस0 जैसे अन्य अस्पतालों में बिना पहुंच सिफारिस का भर्ती नही लिया जाता है तथा हाई रिस्क बताकर बाहर कर दिया जाता है जिनका राजनीतिक पहुंच रहता है उनका बेहतर इलाज होता है इसलिए बोले की की

हम सबको जहां भी है वहां यह नहीं कि हमारे साथ नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव या नाइन्साफी हो रहा हो अवश्य संगठित होकर प्रयास करना आवश्यक ऊपर के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराये बिना विरोध तथा लड़ाई लड़े गरीबों का न्याय नहीं मिल सकता है इस लिए हर गरीब के पास उनकी ताकत है और संविधान है जिससे न्याय प्राप्त किया जा सकता है। हम लोगों ने विरोध किया सरकारी अस्पतालों में बिना निगरानी दवा देखभाल के तथा समय से 102 की गाड़ी नहीं आने से सड़क पर आकर विरोध किया गया उच्च अधिकारियों के आने के बाद हड़ताल जाम को समाप्त किया गया । आज के कार्यशाला का मकसद है कि हम सब जाने कि हमारे लिए स्वास्थ्य की क्या क्या सरकार की योजनाएं सुविधाएं है कैसे बेहतर तरीके से लोगों को लाभ दिलाया जाये। तथा जनगतिविधियों से भी मिलकर बिल भुगतान के लिए पैरवी करें।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की वरिष्ठ महिला दमयन्ती देवी कार्यक्रम में भाग लिया तथा महिलाओं को होने वाले रोग बचाव तथा सरकार की योजनाओं की चर्चा की गांव स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण समिति के कार्य अधिकार वी0एच0एन0सी0 के बारे में महिलाओं की जानकारी दी कि प्रत्येक ग्राम सभा में प्रधान आशा बहु सामाजिक कार्यकर्ता एवं समुदाय की भागीदारी के साथ कमेटी का गठन किया जाता है तथा उनको दस हजार रूपये का फण्ड निर्धारित है दिया जाता है समिति जन आवश्यक खर्चे है उसको उस कार्य के लिए उपयोग कर सकती है आंगनबाडी को 0–5 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पोषाहार पाने का मौलिक हक है सरकार द्वारा यह मुफ्त में सेवा देने के लिए स्वास्थ्यकर्मी रखी है यदि कुपोषण मुक्त समाज बनाना है तो पोषाहार देकर तथा घर

में निगरानी करके बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है साफ सफाई के लिए सरकार विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से खाने से पहले एवं शौच के बाद हैण्ड वास साबुन से हाथ धोना आवश्यक है तथा साफ पानी का उपयोग हमेशा करें क्योकि ज्यादातर बिमारियां गंदे पानी एवं भोजन के आधार होता है हरी सब्जी दाल दलिया का सेवन आवश्य करें सुरक्षित प्रसव के लिए हर गांव में आशा कार्यकर्ता का चयन किया गया है उनकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षित प्रसव के लिए मदद प्रदान करें।

स्वास्थ्यो के देने वाले संस्थाओ की स्थितियो का देखा जाये तो मात्र 37.5 प्रतिशत ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 24 घन्टे खुलते है इन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रो मे अगर उपलब्ध सुविधाओ का बात किया जाये जो मात्र 15.4 प्रतिशत उपकेन्द्रो पर 24 घन्टे विजली एंव 61.5 प्रतिशत उपकेन्द्रो पर पानी की सुविधा मुहैया हो पाती है। आज भी उ0प्र0 मे सरकारी अस्पतालो मे 10 हजार जनसंख्या पर 0.5 डाक्टर है। जिसमे अगर सामाजिक तौर पर देखा जाये तो सरकारी अस्पतालो से स्वास्थ्य सेवाओ को लेने वाले ज्यादातर दलित व अतिवंचित समुदाय के महिलाये एंव बच्चे है यह आंकडा दूसरी तरफ यह भी दर्शाता है कि सरकार की सेवा व्यवस्थाओ पर भी सवाल उठाता हुआ नजर आता है। दलित व अतिवंचित समुदाय के एक बडी जनसंख्या को विशेष गम्भीर बीमारियो के लिये मजबूर होकर प्राईवेट अस्पतालो मे इलाज करवाने के लिये जाना पडता है जहॉ उन्हे भारी भरकम बिल का भुगतान करने के लिये गहने, खेत, घरबार को भी बेच कर प्राईवेट अस्पतालो के बिल का भुगतान करना पडता है। इस कार्याशाला में कुल प्रतिभागीयों की संख्या 317 रही।

निश्कर्ष

कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने अपने सुझाव दिये तथा सभी का यह मानना था कि गरीबी में एक आम व्यक्ति जो आर्थिक तंगी के कारण मंहगे इलाज नहीं करा पा रहा है, सरकारी अस्पतालों में लम्बी लम्बी कतारों में खडे होने के बाद भी अच्छी दवा का न मिलना, डॉक्टर्स की कमी का होना तथा प्राइवेट इलाज कराने पर पैसे की समस्या का होना ही उसके लिए बड़ी समस्या है और सभी ने एक राय होकर यह भी कहा कि समावेषी सुरक्षा स्वास्थ्य फॉरम के माध्यम से सांसदों के समक्ष "पे माई बिल" की मॉग की गई है। उपस्थित प्रतिभागियों ने यह माना अगर सरकार बीमारी पर हुए खर्च के बिल का भुगतान करती है तो इससे मरीज के परिवारीजन की आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं होगी। आपसी सहमती बनाते हुए कहा कि आक्समफैम इण्डिया एवं नव भारतीय नारी विकास समिति के निर्देशन में एवं समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम उ0प्र0 द्वारा की गई पहल को **"पे माई बिल"** मरीज के लिए कारगर सिद्ध होगा। सरकार के जनप्रतिनिधिओं के साथ बडे पैमाने पर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है और इस आवाज को उनके माध्यम से लोक सभा और विधान सभा में भी रखा जा जाये, तो कोई भी बीमार व्यक्ति खर्चे के आभाव में इलाज कराने से नहीं डरेगा। अगर उसके खाते में सरकार सीधा पैसा ट्रासफर करती है तब उसे बहुत सी समस्याओं से मुक्ति मिले

हमारे हित भागी जिनके साथ आनें से अभियान को गति प्राप्त हुआ–

1. महिला
2. पुरूष
3. युवाओं

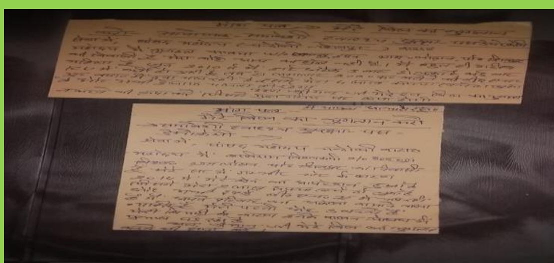

अभियान की उपलब्धियां–

SN	Districts	No. of villages covered	No. of Blocks	No. of Postcard	No. of Patetient	Men	Women	Youths	No of pepole extended support	Covered in Media	No of Events
1	Jaloun	5	1	10	2	268	515	365	1148	0	6
2	Varanasi	8	2	50	14	313	647	775	1735	0	6
3	Unnov	5	1	0	0	346	455	98	899	0	6
4	Kannouj/ Kanpur	15	2	200	15	777	597	255	1629	0	9
6	Hamirpur	5	1	15	3	308	620	185	1113	0	6
7	Jounpur	10	2	30	2	688	1047	209	1944	1	6
8	Ghazipur	50	3	0	0	455	675	176	1306	1	9
10	Ballia	10	2	75	6	879	667	308	1854	0	6
11	Maharajganj	15	3	0	5	345	425	208	978	1	9
12	Firojabad	15	3	50	9	1088	677	345	2110	0	6
13	Mau	5	2	10	6	456	387	250	1093	0	9
		143	22	440	62	5923	6712	3174	15809	3	78

चुनौतियां–

1–प्रत्यासीयों का न मिलना, घबराना।

2–प्रत्यासीयों का टिकट समय से न घोषित न होना।

निश्कर्ष–

मतदाताओं में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अधिकार के प्रति समझ एवं ज्ररूकता बढ़ा एवं प्रत्याशियों के समक्ष अपनी बात को रखने का बल अपना मत देनें से पहले उम्मीदवारों/प्रत्याशियों के द्वारा स्वास्थ्य एंव शिक्षा के प्रतिबद्वता पत्रों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षर का दबाव बना।

कैमरे की नजर में–

प्रत्याशियों के द्वारा हस्ताक्षर–

हस्ताक्षर अभियान–

सामूदायिक बैठक–

प्रतिबद्वता पत्र–

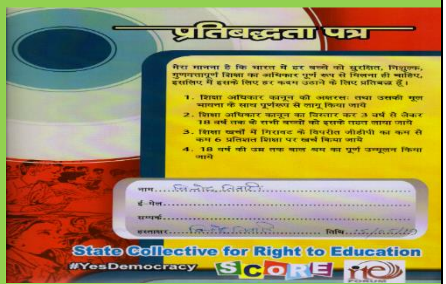

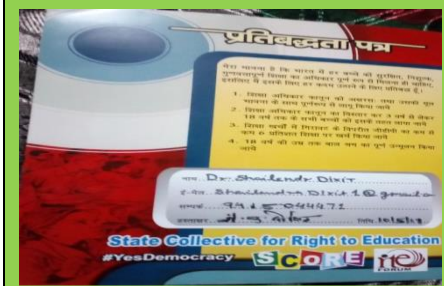

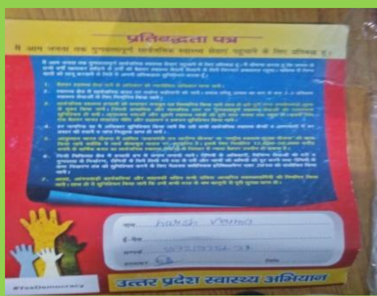

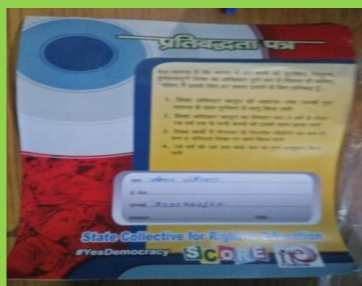

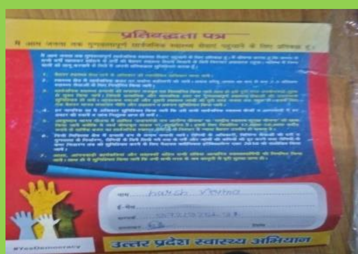

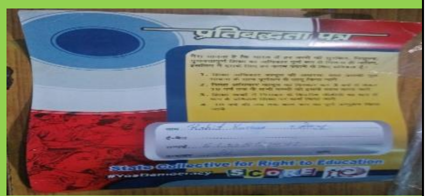

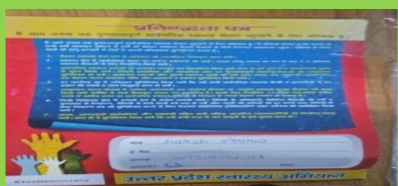

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं
की बेहतरी के लिए
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य अभियान
जिला- बलिया
YES Democracy

YES Democracy

उ.प्र. स्वास्थ्य अभियान

YES Democracy

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओ की बेहतरी की माँग को लेकर
उ.प्र. स्वास्थ्य अभियान
जनपद-जौनपुर
आयोजक-
समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम, उ.प्र.
स्थानीय सहयोगी संस्था
जन विकास संस्थान, नौपेड़वाँ, जौनपुर

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओ की बेहतरी की माँग को लेकर
उ.प्र. स्वास्थ्य अभियान
जनपद-जौनपुर
आयोजक-

स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दे पर युवाओं की सहभागिता।

लखनऊ के स्कुलों/कालेजों में युवाओं के साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दे पर जोरदार चर्चा किया गया इस चर्चे का आयोजन स्थानिय संस्था दस्तक ने किया जो निम्न है–

750 छात्रों के बीच चलाया गया शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर "यस डिमॉक्रेसी अभियान"

यस डिमॉक्रेसी अभियान की भूमिका–

नव भारतीय नारी विकास समिति एवं दस्तक और ऑक्सफेम इंडिया के मिलेजुले प्रयासों से युवाओं में लोकतंत्र के वास्तविक सरोकारों के प्रसार और उन्हें सही मुद्दों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ने के उद्देश्य से लखनऊ के 15 कॉलेज में लगभग 750 छात्रों के बीच यस डिमॉक्रेसी अभियान चलाने की रूपरेखा बनाई गई थीए जिसको अमली जामा पहनाने की शुरुवात 22 अगस्त से हुई। दरअसल उत्तरप्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में लगातार कटौती की जा रही हैए बच्चों की बहुत बड़ी आबादी स्कूल से महरूम है और बाल मजदूरी में लिप्त है। उधर स्वास्थ्य सुविधाएं भी बदहाल हैंए मामूली बीमारी भी किसी को भारी कर्ज़ में धकेल देती है। जबकि किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ शिक्षा और स्वास्थ्य होते हैं। संस्थाओं की समझ थी कि डिग्री कॉलेजेस के युवा पहली बार के वोटर होते हैं या हो रहे होते हैंए अगर यही युवा इन मुद्दों के प्रति सचेत हों और निरंतर इन पर संवाद करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे आम जन मानस के मुद्दे बन सकते हैं और सरकारों का ध्यान भी इनकी बेहतरी के लिये जाएगा।

रणनीति एवं अमल–

इस अभियान के लिये प्रदेश की राजधानी लखनऊ के युवाओं को फोकस किया गया और लिस्ट बनाई गई कि 22 अगस्त से 12 सितंबर के बीच लगभग 15 कॉलेजेस में दस्तक के विभिन्न नेतृत्व कारी साथी-शिक्षक छात्र- छात्राओं से एक खुला संवाद रखेंगेए जहां। मुमकिन होगा प्रोजेक्टर अथवा पोस्टर के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर युवाओं को जागरूक करेंगे तथा उनसे अपील करेंगे कि वो समूह बना कर अपने दोस्तोंएसमुदाय और सोशल मीडिया पर भी समाज के लिये जरूरी इन दोनों मुद्दों पर व्यापक जागरूकता फैलायें।

सभी के लिये समान और गुणवत्ता परक शिक्षा और स्वास्थ्य एक नागरिक अधिकार के रूप में होने चाहिये और इसमे किसी प्रकार का भेदभाव अलोकतांत्रिक भी है।

कॉलेजेस का चयन –

इस अभियान की शुरुवात में वीणा राणा, पूनम ठाकुर, रूपेश ,शांति राय, नीतू रावत, संगीता जैसवाल,दीपक कबीर, शुभम की आठ सदस्यीय टीम ने मुद्दों और उनकी प्रस्तुति पर गहरा विमर्श किया और ये भी तय किया कि छात्रों को भी अभियान में इस तरह जुड़ने के लिये प्रेरित किया जाय कि आगे दूसरे छात्रों के बीच वो स्वयं जिम्मेदारियां लेकर जायँ।

इन कार्यशालाओं की शुरुवात गुरुनानक डिग्री कालेज, एमिटी यूनिवर्सिटी, शकुंतला मिश्र यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंस्टिट्यूट, लखनऊ पब्लिक इंस्टिट्यूट, स्टडी हाल, अवध गर्ल्स डिग्री कालेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दीन दयाल उपाध्याय कालेज, महामाया डिग्री कालेज,

ख्वाज़ा चिश्ती यूनिवर्सिटी, वासुदेव डिग्री कालेज, मीडिया, नगर निगम कालेज, आई टी आई में कार्यशाला- संवाद और हस्ताक्षर अभियान के द्वारा सम्पन हुई जिसमें ऊपर लिखी टीम से सदस्यों ने प्रशिक्षकों के रूप में भागीदारी की।

अभियान की उपलब्धि

इन 750 छात्रों ने न केवल खुद पहल करके इन मुद्दों को आम समाज के मुद्दों में बदलने का वायदा किया बल्कि तय किया कि वो सामूहिक रूप से वाल मैगज़ीन/ पोर्टल/ ब्लाग या सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा भी सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे।

शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और प्रमुख लोगों ने भी इस तरह की मुहिम से जुड़े रहने का वायदा किया।

सभी जगहों में बात चीत के सिलसिले को मुख्यतः दस सूत्री चरणबद्ध कार्यनीति में बदला गया था ताकि सभी जगह एक जैसी ही बात कमोबेश हो सके। ये पॉइंट्स निम्लिखित थे..

1. हर तरफ मीडिया चैनल्स में शोर और वायलेंस है।

2. मेढक मेढकी की शादी, कभी पाकिस्तान , नाग नागिन कभी क्रिकेट ,कभी ऐसी ही गैर जरूरी चीजों का शोर हमे घेरे रहता है।

3. हम नहीं जानते कि आज भी हमारे देश के लाखों बच्चे स्कूल नही जा पातेए उल्टा अपने जीने के लिये मजदूरी कर रहे हैं।

4. हमारे देश मे कोई मज़दूर अगर एक हफ्ते वायरल का भी शिकार हो जाय तो वो कर्ज़ और भुखमरी की गिरफ्त में आ जाता है

5. हमारा सिस्टम लगातार हेल्थ और शिक्षा का बजट कम करता जा रहा हैए शिक्षा और स्वास्थ्य सब मुनाफे पर बेस्ड होती जा रही है इसलिये निजी व्यापारी इसे दुकान की तरह ले रहे हैं।

6. ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ पहुंच वालों और अमीरों के लिये बचेगी। ये हमारी डेमोक्रेसी को ही खत्म कर देगी।

7. हम पढ़ने लिखने वाले छात्र क्या कर सकते हैं।ज़्यादा नही बस हम अपने आस पास के लोगों से, सोशल मीडिया पर अपनी किताबों की बातें जिनमे

डेमोक्रेसी का ज़िक्र है, समानता की बातें हैं ,बराबरी के हक़ हैं, उनको लगातार ज़िक्र में ला सकते हैं।

8. हम अंधविश्वास के खिलाफ अच्छे साहित्य, मनुष्यता और वैज्ञानिक बातों को बढ़ावा दे सकते हैं।

9. हम गैरजरूरी और हिंसा के मुद्दों की बजाय सबकी शिक्षा और स्वास्थ्य और इससे जुड़ी बातों -सूचनाओं को चर्चा में ला सकते हैं।

10. हम छात्र छात्राओं के बीच ऐसी ही सूचनाओं की शेयरिंग का एक प्लैटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के हम अपने आस पास ऐसी जागरूकता फैला सकें।

अगर आप सहमत और इक्छुक हों तो अपने कॉलेज के मार्फत हमारे संपर्क में ज़रूर रहें।

इस प्रकार इस यस डिमोक्रेसी अभियान का पहला चरण पूरा हुआ और अब भविष्य में इन संस्थानों के लगभग 750 छात्रों के साथ लगातार काम करने की ज़रूरत है ताकि लखनऊ शाहर और इसके मार्फत पूरे प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जेंडर बराबरी जैसे मुद्दों पर ही लोकतंत्र की बुनियाद टिकी रहे।

इस प्रकार छात्र–छात्राओं के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मुद्दे एक नया समझ विकसीत करने का प्रयास किया गया, जिससे समाज में एक नया संदेश जाये।

अभियान में सहयोगी सस्थाऐं–

1–चिराग सोसाईटी, फिरोजपुर।
2–ग्रामिण जीवन विकास प्रषिक्षण एवं षोध संस्थान, जालौन/हमीरपुर।
3–वारसी संवा सदन–कन्नौज/कानपुर।
4–प्रतिनिधी–उन्नाव।
5–जन विकास संस्थान, जौनपुर।
6–Purvanchal Rural Development and Training Institute-Ghazipur.
7–समाज सेवा संस्थान, महाराजगंज।
8–निर्बल सेवा समिति, मऊ।
9–दस्तक, लखनऊ।
9–नव भारतीय नारी विकास समिति, बलिया।

प्रेस के कलम से–

मतदाता जागरूकता अभियानका समापन

बख्शा। स्थानीय ब्लॉक के मई गांव में मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह अभियान बख्शा के 18 गांवो में चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान करने के साथ ही साथ गरीब व दलित समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य की मांग को लेकर कुछ प्रमुख दलों के प्रत्याशियों से 11 सूत्रीय मांग पर घोषणा पत्र भी भरवाया गया तथा उस पर उनका हस्ताक्षर भी कराया गया। अभियान के दौरान जागरूकता रैली और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। अभियान के समापन के अवसर पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम के राज्य सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता राजमणि ने कहा की मतदान हमारा संवैधिक अधिकार है। जिसका उपयोग हमें अपने स्व. विवेक से करना चाहिए। हमें इस अधिकार का प्रयोग लालच, बहकावे अथवा दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। खासकर महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देने को कहा। गोष्ठी का संचालन शिव शंकर चौरसिया ने किया। अध्यक्षता कंचन ने किया। अन्य वक्ता के रूप में देवेन्द्र, अमृत लाल, शिव प्रकाश ने भी संबोधित किया। गोष्ठी में मई, बरपुर एवं मग्रेशर के कुल 65 महिला पुरुषो ने प्रतिभाग किया।

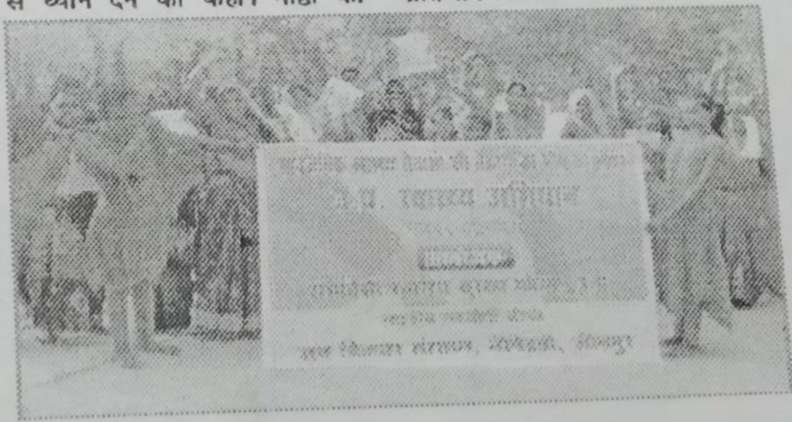

गरीबों के हित में बने समावेशी स्वास्थ सुरक्षा फोरम- डॉ जफर आलम

निशा नरेश संवाददाता

फिरोजाबाद। चिराग सोसायटी एक बैठक का आयोजन गुरूवार को हुआ। जिसमें सोसायटी के अध्यक्ष डॉ जफर आलम से गरीबों के हित में एक समावेशी स्वास्थ सुरक्षा फोरम बनाने की मांग की है।

सोसायटी के अध्यक्ष डॉ जफर आलम ने बैठक को सम्बोधित करते हुये कहा कि हमारा मकसद आम जनता तक सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ज्यादातार गरीब परिवारों में परिवार के किसी सदस्य के बीमारी हो जाने पर उसका उपचार कराने के लिये साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है जिसके एवज में मकान को गिरवी रख दिया जाता है कुछ समय बाद यह मकान उस साहूकार का ही हो जाता है। यही मरीज जब सरकारी अस्पताल में उपचार के लिये जाता है तो उसे सुविधाओं ना होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि बीमारी पर खर्च होने वाला पैसा सीधा मरीज के खाते में जाये। जिसके लिये इस फोरम का बनाया जाना आवश्यक है। बैठक में शाहिद अंसारी, रविन्द्र, जीत चांदना, संगीता पाण्डेय, हसीन, दिलशाद, रूबी अजीज आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन मुख्तार आलम ने किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं
की बेहतरी को लेकर
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य अभियान
जनपद–बलिया
Yes Democracy
समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा फोरम, उ0प्र0
NBNVS
ENCOURAGE, STRUGGLE, PROGRESS
नव भारतीय नारी विकास समिति, बहेरी–बलिया

की प्रस्तुति

....